

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12 |

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2008— चैत्र 1, शक 1930

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक ई-7/3/2008/1 /2.—श्री ओमप्रकाश चौधरी, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा, जिला दुर्ग को दिनांक 15-02-2008 से 29-02-2008 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा, जिला दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक 2010/डी-771/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री इन्द्रकुमार रावत, अधिवक्ता, भानुप्रतापपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट भानुप्रतापपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2170/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गोविंद प्रसाद कौशिक, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2174/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री देवव्रत दत्ता, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2178/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री छेदू सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2184/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री ओमप्रकाश सहाय, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2188/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती नवनीता पाण्डेय, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2190/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री छेदीलाल यादव, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2194/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्वारा श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव।

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक 73/13/ऊ. वि./2008.— राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम सं.-54) की धारा 5 के अन्तर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को एतद्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम सं.-36) की धारा 172 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 29-02-2008 की अवधि से आगामी 31-03-2008 तक निर्वहन हेतु अधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, विशेष सचिव।

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2008

क्रमांक एफ 6-13/2008/वा. कर/पांच.— राज्य शासन एतद्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित वाणिज्यिक कर अधिकारियों को सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री के. आर. ठाकुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरबा वृत्त, कोरबा	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
2.	श्री उदय शंकर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5, रायपुर.	सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
3.	श्री टीकाराम धुर्वे, वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2, दुर्ग.	सहायक आयुक्त, कार्यालय छ. ग. वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर (सचिव के पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर)
4.	श्री तोरण लाल धुव, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3, रायपुर.	सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
5.	श्री आर. पी. सलूजा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर.	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में “छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003” तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ/4-2/2001/1/3, दि. 11-2-2008 द्वारा जारी किए गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक एफ 4-9/2007/23.— राज्य शासन एतद्वारा “छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001” के नियम 13 के अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य 01 जनवरी 2008 से पंचायत प्रणाली को सौंपे जाने के फलस्वरूप इसके पूर्व के जन्म-मृत्यु अभिलेखों के आधार पर “जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969” की धारा 17 के अधीन तलाशी करने, उद्घरण प्रारूप क्रमांक 5 एवं 6 तथा अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रारूप क्रमांक 10 में जारी करने हेतु जन सुविधा की दृष्टि से पूर्व रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पुलिस थाना प्रभारी को अंतरिम रूप से प्राधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक 1971/एफ -13-05/20/08.— छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखंडों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करती है :-

1. उपखंड (ज) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुल सचिव

क्र.	नाम	पता
1.	श्रीमती इन्दु अनन्त	कुल सचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

2. उपखंड (झ) के अंतर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य

क्र.	नाम	पता
1.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	प्राचार्य शासकीय दूधाधारी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर

3. उपखंड (3) के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी

क्र.	नाम	पता
1.	श्री मनोहर पाण्डेय	विशेष सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर

उपरोक्त नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक /क/ वा. /भू. अ./प्र. क्र. 12/अ 82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	परसुलीडीह पटवारी हल्का नं. 96	खसरा नं. (1) रकबा (हेक्टेयर में) (2)	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग-1 रायपुर.	दीनदयाल आवास कालोनी में पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.
			18		0.150
			21/3		0.089
			21/1		
			200		0.202
			199/2		0.057
			198/2		0.041
			199/6		
			199/3		0.036
			29/3		0.101
			29/2		0.020
			29/1		0.136
			30/1		
			31		0.567
			23/2		0.202
		योग	11		1.601

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक /41/ अ. वि. अ./भू-अर्जन/04 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बेलटुकी प. ह. नं. 84	1.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	कोडार जलाशय के बेलटुकी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 04/अ 82/2007-08/सा-1-सात.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बम्हनीडीह	1.754	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कबीरधाम जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 05/अ 82/2007-08/सा-1-सात.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सेमराडीह	12.000 हे.	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सेमराडीह जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक /895/क/भू-अर्जन/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	किरन्दुल	4.817	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)	मे. एस्सार स्टील लिमि. किरन्दुल के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग फाईन ओर स्टोरेज यार्ड एवं ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु. भू-अर्जन.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2008

क्रमांक /903/क/भू-अर्जन/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर (छ. ग.)	शंखनी सेतु 1/4 कि. मी. हेतु पहुंच- मार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बारगांव प. ह. नं. 13	0.081	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	पेण्डी माइनर नं. 5 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बिलारी प. ह. नं. 16	0.685	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बुन्देला माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	चण्डीपारा. प. ह. नं. 03	0.045	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	चण्डीपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कुटराबोड़ प. ह. नं. 14	0.186	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	भदरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम		के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बारगांव प. ह. नं. 13	0.081	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	नेवराबंद माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम		के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	चिस्दा प. ह. नं. 25	0.097	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	हेड़सपुर प. ह. नं. 02	0.036	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	लग्गरी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बिलारी प. ह. नं. 16	0.320	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बिलारी माइनर नं. 2 निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं. 13	0.302	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 02, चाम्पा.	चोरिया सब माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	गोविन्दा प. ह. नं. 16	0.324	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 02, चाम्पा.	चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/14.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भैसो प. ह. नं. 04	0.085	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	डुमरपाली माइनर नं. 5 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/15.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	मेऊ प. ह. नं. 13	0.243	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	बारगांव माइनर नं. 3 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-बड़ा दमाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 20.203 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
4/81	0.971
4/115	0.524
4/26	0.323
520/2	0.494
157/29	0.178
161/4	0.405
4/136	2.023
4/39	0.046
4/7	0.534
161/3	3.246
524	0.141
157/39	0.121
161/6	0.101
4/47	0.038
4/144	0.405
157/5	0.971
513	0.129
4/107	0.364
523/1	0.125
4/49	0.607
4/20	0.251
176/7	0.709
519	0.324
4/110	0.243

(1) (2)

4/31	1.607
4/48	0.928
161/106	0.101
176/3	0.721
521	0.202
4/46	0.607
157/55	0.283
4/117	0.324
161/65	0.129
520/1	1.327
522	0.405
140/34	0.061
157/56	0.235

योग 20.203

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-कसडोल
(ग) नगर/ग्राम-सेमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.01 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
125/1 ख	0.16
125/1 ग	0.41
125/1 ड	0.41
125/1 च	0.28
651/2	0.09
652/3	0.20
650/1	0.02
650/2	0.23
655	0.06
529	0.15
589	1.12
604	
640	
649	
590	0.05
591	0.28
592	0.03
593	0.04
594	0.51
595	0.32
596	0.02
600	0.63

योग 19 5.01

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के गिधौरी शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./08/अ-82/ वर्ष 07-08.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-कचना, प. ह. नं. 110
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1048/1	11.408
1048/1193	2.310
1048/1194	1.672
योग	15.390

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचना, प. ह. नं. 110, रायपुर में मण्डल की कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 01.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.185 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
897/2	0.032
897/1	0.028
898	0.073

(1)	(2)
848/60	0.028
946	0.024
योग	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनिया पाठ माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा ग्रह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-अमरूवा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121/3	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमरूवा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1415	0.049
योग	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.155 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104/1	0.149
104/2	

(1)	(2)	(1)	(2)
126/4	0.093	141/2	0.006
128/6	0.089	141/4	0.154
128/12	0.185	193/2	0.028
142/3	0.028	143/1	0.032
128/2	0.109	132/1 क	0.040
128/3	0.137	128/10	0.054
128/4	0.129	130/5	0.012
128/7	0.041	126/6	0.057
128/11	0.077	118/1	0.012
208/1	0.032	126/1	0.028
128/5	0.097	119/1	0.129
128/9	0.040	141/3	0.057
207/5	0.061	144/2	0.077
208/4	0.094	210/3 ख	0.287
207/2	0.012	204/6	0.097
128/8	0.032	204/5	
129/4	0.012	208/3	0.024
141/1		209/2	0.032
126/3	0.128	208/5	0.016
151/2 क	0.004	210/2	0.041
210/3 ग	0.020	206/2	0.028
134/3	0.012	204/2	0.170
137/1	0.032	125	0.016
139	0.036	142/3	0.008
134/1 ख	0.049	204/3	0.008
134/2		132/1 ख	0.040
136/2		138	0.053
144/1	0.142	210/1 च	0.041
146/1	0.016	207/3	0.070
145/1	0.053	207/6	0.154
204/1	0.028	208/2	0.089
205	0.145	151	0.141
206/1	0.117	207/4	0.162
209/1	0.081	204/4	0.036
135/1	0.045		
139/1 ख		योग	76 5.155
127/5	0.109		
133/2	0.057		
133/3	0.020		
126/2	0.117		
126/7	0.093		
131/2	0.776		
131/1	0.165		
133/1 क	0.153		
133/1 ख			
135/2	0.012		
140/1 क	0.016		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झारमुड़ा शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-22 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-लाखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.000 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

225

9.000

योग

1

9.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-अमली भौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.163 हेक्टेयर

योग

6.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(1)

(2)

51/2

0.125

163/1

0.097

164

0.137

49/1

0.081

47/1

0.089

100/1

0.254

48

0.045

51/1

0.045

82

0.364

79/7

0.342

49/5

0.024

165

0.049

163/3

0.073

97

0.004

101/1

0.110

78

0.304

45

0.194

174

0.861

50

0.166

76

0.579

79/2

0.008

73

0.346

49/3

0.045

180

0.073

46

0.250

163/2

0.073

166

0.739

84/1

0.004

74

0.186

179

0.077

177

0.016

52/2

0.310

79/3

0.024

49/2

0.020

49/4

0.049

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कोसमनारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.181 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95	0.093
133/2	0.202
150/1	0.595
92/4	0.186
105/1	0.141
93	0.161
148/2	0.197
91	0.298
87	1.900
149/1	0.053
148/3	0.262
146/6	0.093
योग	4.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कलमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.441 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
376/1	0.113
381/8	0.350
381/7	0.795
387/6	0.016
387/1	0.324
385/1	0.169
369/3	0.162
370	0.045
381/9	0.101
377	0.125
381/10	0.113
387/8	0.065
387/7	0.020
390/1	0.185
371/2	0.077
376/2	0.011
378	0.057
387/3	0.105
387/5	0.169
385/2	0.057
369/1	0.304
379/1	0.012
योग	3.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-झारमुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.034 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

179/1

0.008

147

0.065

147

0.166

890

142

0.008

32/1

0.105

141/1

0.190

137

0.008

141/2

0.106

106/2

0.113

144/1

0.008

144/3

0.020

101

0.041

106/1

0.094

107/1

0.089

34

0.024

25

0.053

178/1

0.008

7/1

0.458

7/2

13/1

0.138

36

0.073

146

0.351

60

0.142

303

0.077

104

0.097

107/2

0.174

10

0.082

(1)

(2)

103

0.016

131/1

0.206

106/3

0.113

62

0.040

8

0.036

40/1

0.326

178/2

0.008

9/1

0.437

13/2

133/1

0.506

37

0.081

145

0.279

109

0.012

144/2

0.125

105

0.126

108

0.036

140

0.008

131/2

0.129

61

0.668

107/3

0.134

63

0.032

31/1

0.234

21

0.020

30/1

0.146

17/2

0.097

26/6

0.336

769/1 क

0.032

11

0.367

288

0.085

41

0.016

26/2

0.060

30/2

289

0.366

294

0.036

301

0.450

302/1

0.065

19/5

0.246

201/1

0.105

148

0.162

771/1

0.041

201/2

0.154

योग

9.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-तड़ोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 8.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1/1

0.611

25/2

0.040

25/4

0.040

128/2 क

0.024

23/4

0.097

20/1

0.133

31

0.396

32/4

0.118

129

0.024

135/2 क

0.033

142/4

0.121

134/3

0.129

142/7

0.194

142/2

0.303

144/2

0.198

26/1

0.254

25/3 क

0.069

30/2 ख

0.194

30/2 क

0.323

28

0.004

40/1

0.202

30/2 ड

0.052

32/2

0.170

32/5

0.008

131

0.016

135/2 ख

0.028

142/3

0.028

(1)

(2)

134/1 क

0.186

134/2

143/1 क

0.053

143/3

0.061

148/3

149/3

152/2 घ

0.134

26/2

0.105

29/2 क

0.097

127/2 क

0.101

23/2

0.041

23/3

0.190

24

30/1

0.379

32/3

0.032

128/1

0.648

133/1

0.676

135/1 क

0.081

143/1 ख

0.121

142/1 क

0.142

135/1 ख

0.073

143/2

0.109

153/4 क

0.012

144/1

0.405

157

0.363

158

0.202

159

160

4/1

0.073

135/2 ग

0.016

152/2 ग

0.134

152/2 ड

0.133

29/2 ख

0.012

30/2 घ

0.032

30/2 ग

127/2 ख

0.045

128/ ख

कुल योग

8.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-जकेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.271 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

375

0.125

378

0.133

391/1

0.036

441/3

0.137

438/1

0.073

432

0.206

415/1

0.024

417/2

0.020

412/3

0.101

443/1

0.209

433/2

0.243

406

0.012

409/3

0.073

376

0.145

389

0.081

390/2

0.210

441/1

0.034

439

0.218

422

0.307

421

0.020

412/4

0.012

415/2

0.057

437/2

0.016

390/1

0.628

410

0.097

444/2

0.610

377

0.202

(1)

(2)

441/2

0.089

443/3

0.148

420

0.840

431

0.198

412/1

0.182

417/1

0.012

412/2

0.101

437/1

0.020

443/2

0.161

414

0.410

408/1

0.081

योग

6.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोडातराई

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

588/10

0.178

596

0.012

601/1

0.089

572/1

0.073

512/1

0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
512/2	0.008		
517/2	0.016	133/3	0.121
520	0.016	261/3	
521	0.339	139/2	0.016
133/2	0.113	148/9	0.121
261/2		263	0.073
484	0.073	515/2	0.105
524/1	0.036	516/2	
483/2	0.012	511/2	0.012
592	0.210	533/1	0.202
598	0.162	522	0.218
597	0.145	134/1	0.041
604/1	0.073	485	0.202
513/1	0.101	267/2	0.057
534	0.142	486/2	0.129
523/1	0.049	593	0.247
148/4	0.057	601/2	0.089
410/2	0.218	601/3	0.097
482	0.004	510/1	0.008
492/2	0.041	517/1	0.129
411/3	0.101	271/2	0.004
411/1	0.012	535	0.065
266/1	0.057	273/8	0.085
137	0.077	269/3	0.020
135/2	0.113	262/1	0.061
532/2	0.020	132/1	0.008
160/6	0.129	146/2	0.137
483/1	0.008	412/15	0.008
268/3	0.049	412/16	
588/9	0.077	412/19	0.041
149/1	0.081	411/2	0.032
589	0.202	270	0.045
588/7	0.101	262/3	0.352
599/6	0.254	138	0.049
600/6		523/2	0.081
147	0.367	133/4	0.325
571/2	0.020	261/4	
532/1	0.020	148/6	0.178
269/4	0.036	486/1	0.202
269/5	0.036	588/8	0.178
136/2	0.461	599/10	0.041
599/7	0.049	600/10	
600/7		602	0.008
487/1	0.081	571/3	0.016
487/2	0.081	269/1	0.036
490/1	0.020	273/7	0.028
266/9	0.298	269/6	0.020
262/2	0.089	136/1	0.202
		150/1 ख	0.028

(1)	(2)	(3)
269/2	0.028	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
258/1	0.081	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
587/3	0.012	
योग	9.245	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

